[श्री राम नरेश यादव]

लेकिन नाफेड की व्यवस्था कागज पर ही रह गई है। कहीं पर भी नाफेड के द्वारा खरीद नहीं हो रही है। इसका असर यह पड़ रहा है कि देहातों में किसान मजबूर होकर 50-50 रुपए क्वींटल के भाव पर आलू बेच रहा है। दूसरे कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था नहीं है। दूसरे कोल्ड स्टोरेज वालों ने अपने शीत गृहों पर यह लेबल लगा दिये हैं कि आलू का भंडारण नहीं होगा। इसका नतीजा यह हो गया है कि आलू के बोरे महीनों बाहर पड़े रहते हैं और आलू सड़ रहा है, उस पर दुर्गन्ध आ रही है। इस प्रकार से किसान मारा जा रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने जब आलू का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसके संकट के निवारण के लिए, उसकी खरीद के लिए, कोई उद्योग नहीं लगाया है। इसलिए मेरी यह मांग है कि सरकार ने जो 70 रुपए क्वींटल नाफेड के द्वारा खरीदने की बात की है, वह दाम बहुत कम हैं। जैसाकि कानपुर के प्रौद्योगिकी और विज्ञान महाविद्यालय ने दो साल पहले 87 रुपए नियत किया था, लेकिन सरकार ने सौ रुपए भी नहीं किया और 70 रुपए में सरकार खरीद भी नहीं रही है। मतलब यह है कि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। जानबूझ कर किसानों के सामने यह समस्या पैदा की जा रही है कि वे पैदावार न बढ़ायें। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसानों का आलू खरीदने की व्यवस्था करे ताकि जो 60 लाख टन आलू प्रदेश में पैदा हुआ है वह बाहर भेज कर बेचा जा सके। मेरी सरकार से यह भी मांग है कि इन इलाकों में सरकार इंडस्ट्री लगाने पर गम्भीरता से विचार करे और इसके लिए योजना बनाए। आलू उत्पादक किसान आज जिस तरह से मारा जा रहा है और इस सरकार के राज में उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनको दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए। इन क्षेत्रों में जन शक्ति भी अपार है। किसानों और मजदूरों को काम दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों में उद्योग लगाये जायें। इन शब्दों के साथ मेरा सरकार से आग्रह है कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जायें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश): मायवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी यादव साहब ने जो स्पेशल मेंशन उठाया है, आप जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज वालों को सरकार बड़े पैमाने पर बिजली देती है, कर्जा देती है, उनकी स्थापना में सहायता देती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज वाले अपने भंडारों में आलू नहीं रखते हैं, बल्कि अब उन्होंने गुड़ रखना शुरू कर दिया है। उसका नतीजा यह होता है कि सस्ते भाव पर गुड़ रख लेते हैं और बाद में ऊंचे भाव पर बेच देते हैं। इसका नतीजा यह भी हो रहा है कि जो पैरिशेबल कमोडिटीज हैं वे बाहर पड़ी रहती हैं। इसलिए मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि हर हालत में इन कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाय और उसके बाद में कोई अन्य चीज रखी जाय। हर हालात में आलू के रखने की व्यवस्था की जाय।

Plight of Labourers working in Salt Industry in Gujarat

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात): मान्यवर, आज से 58 वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तु नमक पर लगाये कर तथा नमक उत्पादन के एकाधिकार के विरुद्ध आन्दोलन चलाया तथा ऐतिहासिक डांडी कूंच का आयोजन किया। इसी नमक उत्पादन से संबंधित मजदूरों की दयनीय स्थिति के उन्मूलन के संबंध में मैं इस विशेष उल्लेख से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, समग्र देश में 70 लाख टन नमक का उत्पादन होता है जिसका 60 से 66 प्रतिशत उत्पादन गुजरात करता है और

अधिकतर यह सुरेन्द्रनगर जिले के 46 गांवों में यमरजार नमक पकाने वाले जिन्हें गुजरात में अगरीये कहा जाता है, वह करते हैं ।

मान्यवर, सफेद नमक पकाने वाले ये अगरीये काली मजदूरी करते हैं । रण में अरब सागर के पानी को जमा करने के लिये ये 30–40 फीट के गड्ढे खोदते हैं और जब ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं तब उसे बाहर निकालने के लिये पम्प सैटों का इस्तेमाल करना पड़ता है । किन्तु ये सैट भी इन्हें ब्याज पर पैसे देकर लाने पड़ते हैं । मान्यवर, इन लोगों की हालत नर्क के समान है । चौबीसों घंटे खारे, नमक वाले पानी में रहने से इन्हें चमड़ी का रोग हो जाता है । पांवों में चीरे पड़ जाते हैं और लम्बे समय में पैर संवेदनहीन भी हो जाते हैं और सबसे दयनीय बात तो यह है कि मृत्यु के पश्चात् उनके पांव चिता में भी नहीं जल पाते । अत्यन्त शारीरिक यातनाओं के पश्चात् भी उन्हें न्यूनतम वेतन भी प्राप्त नहीं होता । कुछ भी मिलता है वह बड़े व्यापारियों की दया से मिलता है । सतत पानी में रहने के बावजूद इन्हें नहाने और पाने के पानी के लिये प्रतिवर्ष 4 से 7 लाख रुपयों के खर्च पर टैंकरों से पानी मिलता है । अस्थायी झोंपड़ियों में ये रहते हैं तथा उनके बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । सहकारी संस्थाओं के बावजूद स्थापित हितों द्वारा उनका भयंकर शोषण होता है । मान्यवर, रेल वैगन समय पर उपलब्ध न होने के कारण नमक सस्ते दामों पर इन्हें बेच देना पड़ता है ।

मान्यवर, नमक केन्द्र का विषय है और उद्योग विभाग को इन समस्याओं का हल करना है किन्तु वह तो गुजरात के बजाय अपना कार्यालय जयपुर में रखे बैठे हैं । मैं इस केन्द्र को गुजरात में स्थानान्तरित करने की मांग करता हूं । मान्यवर, नमक कर की आय से 20 प्रतिशत राशि इन नमक पकाने वाले मजदूरों पर उनके पेयजल, आवास तथा उनके स्वास्थ्य पर खर्च करने की नीति जो है उसका कोई अमलीकरण नहीं है । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि उद्योग मंत्रालय नमक कर की आय के 20 प्रतिशत से अधिक के आवंटन का आयोजन करके इन गरीब शोषित मजदूरों को सहायता प्रदान करे और उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न करे ।

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat); Sir, while associating myself with the Special Mention made by my colleague, Shri Mirza Irshadbaig, I would like to draw the attention of the Government, particularly, the Ministry of Industry, to two aspects. Firstly, the Varadarajan Committee Report on Central Salt Cess should be immediately implemented by the Union Government. Secondly, the- collection of this Cess should be given to the State Government so that it is properly spent for the welfare of the workers employed on the salt pans.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir. I would like to draw the attention, of the Minister of Finance that as they have given life insurance cover to the farm labour, the same should be extended to these workers in the salt industry so that they will also be benefited like the farm labour. I would request the hon. Minister of Finance to consider this.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : माननीय मीर्जा इर्शादबेग जी ने नमक बनाने वाले गरीब लोगों की मानवीय समस्याओं जी तरफ जो सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित किया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दे ।

SHRI RAJUBHAI A. PARMAH (Gujarat): Sir, I also associate myself with the views expressed by hon. Member, Sir Irshadbaig, because I come from the same District about which he has mentioned.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, the hon. Member has pointed out that the Minimum Wages Act has not been implemented in the case of these workers in the salt industry. This is a serious matter. Lakhs of people are employed in this industry. I would request the hon. Minister concerned to see that the Minimum Wages Act is enforced strictly in the case of these workers also in Gujarat and other places.

Malfunctioning; of Telephone Department in Meerut

श्री शाम्भि त्यागी : (उत्तर प्रदेश") . मान्यवर, मेरठ महानगर में टेलीफ न सेवा मह्नीनों से गड़बड चल रही है। तमाम ल न परे ान हैं । स्थानीय काल मिलना भी कठिन है । टेलीफोन का डेड हो जाना, लगातार डायल टोन आना, ट्रिपिंग होना, आवाज धीमी होना, यह शिकायतें लगातार जारी हैं और यह मेरठ की बात है । दिनभर में सभी टेलीफोन एक न एक खराबी क शिकार हो जाते हैं । विभागीय कर्मचारियों का दोष नहीं है । मशीनों की खराबी है । एक पुराना एक्सचेंज है वह करीब करीब बेकार हो गया है । एक नया एक्सचेंज लगा है वह भी करीब करीब बेकार है । मेरठ से एस०टी०डी० काल मिलना भी करीब करीब असम्भव होता है मैं अब दिल्ली की बात भी कहूंग और मैं जा बात कह रहा हूं इसकी वर्मा जी बाद में ताईद भी करेंगे । दिल्ली से मेरठ जब हम एस०टी०डी० करते हैं तो दिन भर में यदि हम 100 नम्बर ट्राई करें तो एक भी नम्बर नहीं मिलता है । यह तो एस०टी०डी० सेवा की हालत है दिल्ली और मेरठ की । यही बात दिल्ली से गाजियाबाद की है । मेरा संचार मन्त्री जी से यह निवेदन है कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज आ गये हैं मेरठ में अपने विभाग को ठीक करें वहां की संचार व्यवस्था को ठीक करें और दिल्ली मेरठ और दिल्ली गाजियाबाद की जो टेलीफोन लाइनें हैं इनको भी ठीक करें। पब्लिक को बहुत तकलीफ है । हम लोगों को बहुत दिक्कत है और सरकार को इन तकलीफों को अविलम्ब दूर करना चाहियें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मुज्जफरनगर की हालत तो इससे भी खराब है ।

Brainwashing of Indian prisoners in Pakistan jails

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry); I would like to inform the House about a very important matter relating to brainwashing of Indian prisoners in Pakistan jails. Actually, there are 6 jails in Pakistan including Mianwali where about 238 prisoners were held. Out of this number 38 were prisoners .from Punjab, 37 from 3arnrmi and Kashmir and other prisoners were from other States. Actually about 110 detenus were released at Wagha Indo-Pakistan border on March 24. They brought to light that the Pakistan authorities had been consistently giving disinformation about the Indian Government dealing with the Punjab situation. Those who have been released were told that the Sikh youths were being killed by the Indian paramilitary forces in Punjab. They have also been telling the prisoners who have been released that if they went to India, they would be tortured by the Government of India. This kind of disinformation by Pakistan is given to the Indian prisoners in Pakistan jails. They are giving wrong information to the Indian prisoners as to what is happening in India. Actually, the Pakistan intelligence agencies have been visiting the jails where in Indian political prisoners and other prisoners have been locked up. They have been giving the information that in Punjab a situation has arisen where no common, man is able to live. That kind 6f information i" being given to them and to those prisoners who have been released recently-

I would, therefore, like to seek two clarifications and a reply from the hon. Minister. Firstly, the Indian Government should tak° immediate steps for release of PH the political prisoners and other